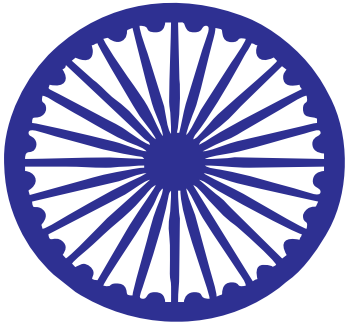




नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01

अंक : 039

दि. 11.11.2025,

मंगलवार

पाना : 04

किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneha Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 • Email : navsarjansanskriti2016@gmail.com • Email : navsarjansanskriti2016@yahoo.com • Website : www.navsarjansanskriti.com

तिरुपति मंदिर लड्डु घोटाला : 250 करोड़ का 'मिलावटी विश्वास', 68 लाख किलो नकली घी से चढ़ा प्रसाद, पांच साल तक चलता रहा खेल

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की आस्था के सबसे बड़े प्रतीकों में गिने जाने वाले तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) में प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाने वाले 'श्रीवारी लड्डू' की पवित्रता पर गहरा दाग लग गया है। सीबीआई की जांच में यह खुलासा हुआ है कि पिछले पांच वर्षों (2019 से 2024) तक मंदिर में भगवान वैकटेश्वर को चढ़ाए जाने वाले लड्डू में नकली घी का इस्तेमाल होता रहा। जांच एजेंसी के मुताबिक, उत्तराखंड की भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी ने मंदिर को 68 लाख किलो मिलावटी घी और मक्खन की सप्लाई की, जिसकी कुल कीमत लगभग 250 करोड़ रुपये है। यह नकली घी

असली दूध या मक्खन से नहीं, बल्कि मोनोडाईग्लिसराइड्स, एसिटिक एसिड एस्टर और अन्य रासायनिक पदार्थों को मिलाकर तैयार किया गया था। सीबीआई की स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (SIT) ने बताया कि इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश आरोपी अजय कुमार सुगंध की गिरफ्तारी के बाद हुआ, जिसने इन रासायनिक पदार्थों की आपूर्ति डेयरी को की थी। यह भी सामने आया कि इस डेयरी ने कभी वास्तविक दूध की खरीदारी नहीं की, बल्कि झूठे रिकॉर्ड बनाकर अपने कारखाने में कृत्रिम घी का उत्पादन किया और उसे 'शुद्ध देशी घी' के रूप में मंदिर को भेजा। जांच में यह भी पाया गया कि

जब टीटीडी ने जुलाई 2023 में चार टैंकर घी को रिजेक्ट किया — क्योंकि उसमें पशु वसा की मिलावट पाई गई थी — तब भी भोले बाबा डेयरी ने उस घी को नए लेबल लगाकर दोबारा मंदिर को भेज दिया। इसके लिए उन्होंने दक्षिण भारत में मौजूद अपनी सहायक कंपनियों के नाम का इस्तेमाल किया, जिनमें वैष्णवी रासायनिक पदार्थों की आपूर्ति डेयरी को करती थी। (तिरुपति), मालगंगा डेयरी (उत्तर प्रदेश) और ए.आर. डेयरी फूड्स (तमिलनाडु) शामिल हैं। तमिलनाडु के डीडिगुल स्थित ए.आर. डेयरी प्लांट से जब सीबीआई और एफएसएसएआई की संयुक्त टीम ने जांच की, तो पाया गया कि रिजेक्ट घी स्थानीय



स्टोन क्रशिंग यूनिट में भेजा गया था, जो वैष्णवी डेयरी के पास स्थित थी। वहां इस घी को प्रोसेस कर नया लेबल लगाया गया



और फिर से तिरुपति मंदिर को सप्लाई कर दिया गया। यही घी मंदिर के लड्डू प्रसाद में उपयोग हुआ, जो करोड़ों श्रद्धालुओं को

दिया गया। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह केवल एक आर्थिक घोटाला नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और जनविश्वास के साथ धोखाधड़ी है। एजेंसी अब यह जांच कर रही है कि TTD के किन वरिष्ठ अधिकारियों और आपूर्तिकर्ताओं की मिलीभगत इस पूरे नेटवर्क में रही। इस मामले की गुंज देशभर में सुनाई दी, जिसके बाद इसे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया। शीर्ष अदालत ने बीते वर्ष अक्टूबर में टिप्पणी की थी कि "यह मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है, इसे राजनीतिक नाटक न बनाया जाए।" अदालत ने इसके बाद एसआईटी जांच के

निर्देश दिए थे, जिससे मंदिर प्रबंधन और आपूर्तिकर्ताओं की जवाबदेही तय की जा सके। विवाद के बाद मंदिर प्रशासन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) ने बयान जारी करते हुए कहा कि अब मंदिर में केवल शुद्ध और प्रमाणित घी का ही उपयोग किया जा रहा है और श्रीवारी लड्डू की पवित्रता व दिव्यता अब पूरी तरह बेदाग है। प्रशासन ने कहा कि वे इस पवित्रता को बनाए रखने के लिए आगे भी सख्त कदम उठाते रहेंगे। मामले की जांच के समानांतर, मंदिर प्रबंधन ने अपने परिसर में अनुशासन भंग करने वाले दो आउटसोर्स कर्मचारियों की

सेवा समाप्त कर दी। ये दोनों कर्मचारी — रामास्वामी और सरसम्मा — अलीपिरी के पास मांसाहारी भोजन करते हुए पकड़े गए थे। TTD ने इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। आंध्र प्रदेश चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट की धारा 114 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। इस पूरे प्रकरण ने न केवल तिरुपति मंदिर की खाद्य आपूर्ति प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं, बल्कि श्रद्धालुओं के मन में गहरी चिंता भी पैदा की है। करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ा यह मामला अब धर्म, व्यवसाय और नैतिकता — तीनों की कसौटी पर परखा जा रहा है।

झारखंड उपचुनाव से पहले घमासान: घाटशिला में वोटिंग से पहले कथित रूप से बंटा पैसा, बीजेपी ने JMM पर लगाया गंभीर आरोप

(जीएनएस)। रांची। झारखंड के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले सियासी माहौल अचानक गर्मा गया है। मतदान से एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुो) पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि रात के अंधेरे में मतदाताओं के बीच पैसा बांटे जा रहे हैं, ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। इस आरोप ने चुनाव आयोग और प्रशासन दोनों के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है।



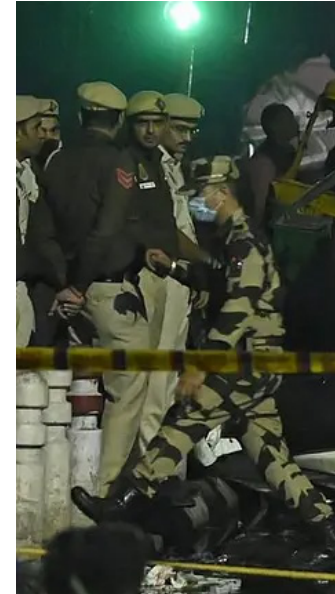
रामदास सोरेन के निधन के बाद हो रहा है। झामुो ने उनके पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन को उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को मैदान में उतारा है। इस चुनाव को राज्य की सत्ता समीकरणों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि परिणाम यह तय कर सकते हैं कि जनमत झामुो सरकार के साथ है या उसके खिलाफ। वहीं, झामुो की ओर से पार्टी महासचिव एवं प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने इन आरोपों को सिरि से खारिज करते हुए भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि "भाजपा को पहले से पता है कि वह चुनाव हारने वाली है, इसलिए अब झूठे आरोप लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है।" घाटशिला की जनता दिशोम गुरु शिबू सोरेन और अपने दिवंगत नेता रामदास सोरेन को भी भारी मतों से जिताने जा रही है। भट्टाचार्य ने दावा किया कि झामुो को अपने उम्मीदवार की जीत पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि "लोग झामुो की नीतियों, विकास

कायों और स्थानीय नेतृत्व पर विश्वास करते हैं। इस उपचुनाव में जनता भावनात्मक रूप से पार्टी के साथ है।"

दूसरी ओर, भाजपा का कहना है कि झामुो-नीत गठबंधन सरकार ने राज्य को "लूट और भ्रष्टाचार की दलदल" में धकेल दिया है। आदिव्य और धनबल नहीं, जनबल की जीत होगी। साहू ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि "रेत, पत्थर और खनन माफिया" सरकार के संरक्षण में खुलेआम लूट मचा रहे हैं और गरीब जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने दावा किया कि झारखंड की जनता अब इस सरकार से पूरी तरह निराश है और घाटशिला का यह उपचुनाव जनता की नाराजगी को साफ तौर पर दिखाएगा। साहू ने कहा, "लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार धनबल नहीं, जनबल की जीत होगी।" घाटशिला में मतदान 11 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में होगा। चुनाव आयोग ने सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है ताकि किसी भी तरह की अनियमितता या हिंसा को रोका जा सके। मतगणना 14 नवंबर को होगी, जिसके बाद यह तय होगा कि स्थान परगना की इस महत्वपूर्ण सीट पर किसकी जीत होती है—शिबू सोरेन की विरासत या भाजपा की चुनौती।

(जीएनएस)। दिल्ली। राजधानी में सोमवार शाम उस वक़्त अफरातफरी मच गई जब ऐतिहासिक लाल किला के पास खड़ी एक कार में अचानक जोरदार धमाका हो गया। यह विस्फोट इतना भीषण था कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई। धमाके के तुरंत बाद आसपास खड़ी कई गाड़ियों में आग लग गई, जिससे देखते ही देखते पूरा क्षेत्र धुएं से भर गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि कई मीटर दूर खड़ी गाड़ियों की खिड़कियां टूट गईं और आसपास की इमारतों की दीवारों में कंपन महसूस किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है जबकि 7 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को पास के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। अस्पताल के अधीक्षक ने मृतकों की संख्या की पुष्टि करते हुए कहा कि घायलों में कुछ की हालत बेहद गंभीर है, जिन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। विस्फोट शाम करीब साढ़े छह बजे के आसपास लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास



हुआ। चश्मदीनों ने बताया कि जैसे ही धमाका हुआ, आसपास खड़ी कारें और दोपहिया वाहन आग की लपटों में घिर गए। कुछ ही पलों में पूरा इलाका दहशत और चीख-पुकार से भर गया। लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 15 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। पुलिस ने तुरंत इलाके

को घेर लिया और पूरा क्षेत्र कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। सामान्य वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है, जबकि आसपास के बाजारों को यह भी जांच कर रही है कि कहीं कार में आईईडी (Improvised Explosive Device) तो नहीं कर दिया है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और बम निरोधक दस्ते के साथ फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच के

अनुसार, विस्फोट एक पार्क की गई कार के अंदर हुआ, हालांकि विस्फोट के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं कार में आईईडी (Improvised Explosive Device) तो नहीं रखी गई थी। लाल किला इलाका दिल्ली के सबसे पर पड़ोस है और बम निरोधक दस्ते के साथ फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच के

पर्यटक, स्थानीय लोग और बाजार में खरीदारी करने वाले सैकड़ों लोग मौजूद रहते हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है। धमाके के बाद दिल्ली के कई हिस्सों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मेट्रो स्टेशनों, प्रमुख बाजारों और सरकारी इमारतों के आसपास पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई है। जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि यह धमाका दुर्घटनावश हुआ या किसी सुनिश्चित साजिश का हिस्सा था। इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी घटना पर रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि "यह गंभीर मामला है। प्रारंभिक जांच जारी है, और किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा चूक सामने आने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।" लाल किला, जो न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश की सुरक्षा और सांस्कृतिक धरोहर का यह भी जांच कर रही है कि कहीं कार में आईईडी (Improvised Explosive Device) तो नहीं रखी गई थी। लाल किला इलाका दिल्ली के सबसे पर पड़ोस है और बम निरोधक दस्ते के साथ फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच के

ऑपरेशन 'आहट' में बड़ी सफलता: पूर्व रेलवे आरपीएफ ने 45 मानव तस्करों को दबोचा, 108 पीड़ितों को मुक्त कराया

(जीएनएस)। कोलकाता। पूर्व रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने मानव तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान "ऑपरेशन आहट" के तहत बीते दस महीनों में बड़ी सफलता हासिल की है। एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, इस अभियान के दौरान 31 अक्टूबर तक आरपीएफ ने 45 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया और चार मंडलों में फैले नेटवर्क से 92 किशोरों सहित कुल 108 लोगों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया। इस कार्रवाई ने न केवल पूर्वी भारत में सक्रिय मानव तस्करी गिरोहों को कराड़ झटका दिया है, बल्कि रेलवे सुरक्षा बल की सतर्कता और मानवीय संवेदनशीलता को भी उजागर किया है। आरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान 1 जनवरी से शुरू होकर लगातार जारी है। विशेष टीमों को हावड़ा, सियालदह, आसनसोल और मायदा मंडलों में सक्रिय तस्करी नेटवर्क पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया था। अधिकारियों के अनुसार, मानव तस्करी अक्सर गरीब परिवारों के बच्चों और किशोरों को बहलाकर या नौकरी के लालच में फंसाकर उन्हें बड़े शहरों में जबरन मजदूरी या देह व्यापार में धकेल देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में यह नेटवर्क पूर्वी भारत से दिल्ली, मुंबई और दक्षिण भारत के हिस्सों तक फैल चुका था, जिसे रोकने के लिए आरपीएफ ने रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में गहन निगरानी अभियान चलाया। पूर्व रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस साल जनवरी से अक्टूबर तक "ऑपरेशन नन्हे फरिस्ट" के तहत भी बड़ी संख्या में बच्चों को बचाया गया है। इस विशेष अभियान में उन नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है जो अकेले यात्रा कर रहे हों, गुमशुदा हों या जिनकी देखभाल और संरक्षण की जरूरत हो। अधिकारी ने बताया कि अब तक कुल 976 बच्चों को सुरक्षित किया गया है, जिनमें 591 लड़के और 385 लड़कियां शामिल हैं। इन

बच्चों को काउंसिलिंग और प्राथमिक चिकित्सा के बाद चाइल्ड वेलफेयर कमिटियों को सौंपा गया। अधिकारियों ने बताया कि आरपीएफ की टीमें लगातार रेलवे स्टेशनों, प्लेटफॉर्मों और ट्रेनों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखती हैं। कई मामलों में यात्रियों की सतर्कता और सूचना देने की तत्परता से भी बच्चों की जान बची है। हावड़ा और सियालदह जैसे बड़े स्टेशनों पर विशेष 'विजिलेंस यूनिट' बनाई गई है, जो मानव तस्करी से जुड़े संदेहास्पद मामलों की तुरंत जांच करती हैं। इन अभियानों के दौरान कई बार बच्चों को बस टिकट या फर्जी पहचान पत्रों के साथ पकड़ा गया, जिससे पूरे गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। आरपीएफ ने बताया कि गिरफ्तार 45 मानव तस्करों के खिलाफ विस्तृत जांच जारी है। इनमें से कई आरोपी ऐसे गिरोहों से जुड़े हैं जो बिहार, झारखंड, ओडिशा और बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में गरीब परिवारों को निशाना बनाते थे। इन तस्करों के पास से मोबाइल फोन, नकली बैंक कार्ड, पहचान पत्र और टिकट बुकिंग रिकॉर्ड बरामद किए गए हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि कई मामलों में पीड़ितों को काम दिलाने के नाम पर ट्रेनों से दिल्ली या मुंबई भेजा जाता था, जहां उन्हें बंधुआ मजदूरी या अवैध काम में डोका दिया जाता था। पूर्व रेलवे के मुख्य सुरक्षा आयुक्त ने कहा कि रेलवे सुरक्षा बल सिर्फ रेलवे संपत्ति की रक्षा नहीं करता, बल्कि मानवता की सुरक्षा भी उसकी प्रमुख जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि "ऑपरेशन आहट" और "ऑपरेशन नन्हे फरिस्ट" जैसे अभियानों को और सशक्त बनाने के लिए आधुनिक तकनीक, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)-आधारित ट्रैकिंग सिस्टम को शामिल किया जा रहा है। इससे संदिग्ध गतिविधियों की पहचान तुरंत हो सकेगी।

महिलाएं हैं देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछाकब लागू होगा महिला आरक्षण कानून

(जीएनएस)। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महिला आरक्षण कानून 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023' के लागू होने में हो रही देरी पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने इस सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि भारत में महिलाएं वास्तव में सबसे बड़ा "अल्पसंख्यक वर्ग" हैं, जहां जो आबादी का लगभग 48 प्रतिशत हिस्सा होने के बावजूद राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अब भी पिछड़ी हुई हैं। न्यायमूर्ति बी. वी. नागरला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की खंडपीठ ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह कानून केवल संख्या का नहीं, बल्कि समानता और न्याय के संवैधानिक आदर्शों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अदालत ने कहा, "भारत के संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों के लिए राजनीतिक और सामाजिक समानता की गारंटी दी गई है। सवाल यह है कि इस देश में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक कौन है? महिलाएं — जिनकी आवाज अब भी पर्याप्त रूप से संसद और विधानसभाओं में नहीं सुनी जाती।" अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों को सुरक्षित रखना संविधान में निहित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। उनका कहना है कि 75 वर्षों बाद भी जब संसद में महिलाओं की संख्या 15 प्रतिशत से कम है, तब 'नारी शक्ति वंदन' को प्रतीक्षा की बेड़ियों में बांधकर रखना न्यायसंगत नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र से चार स्पष्ट सवालों के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि यदि आवश्यक हुआ, तो इस विषय पर व्यापक जनहित सुनवाई आयोजित की जा सकती है, क्योंकि यह मुद्दा देश की आधी आबादी की राजनीतिक भागीदारी से जुड़ा है — जो लोकतंत्र की आत्मा है।

नहीं मिल पाएगा। अदालत ने केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि वह महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है, और क्या इसे अगली लोकसभा या विधानसभा चुनावों से पहले लागू किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सितंबर 2023 में संसद ने भारी बहुमत से पारित किया था। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। लेकिन सरकार ने इसे नए परिसीमन के बाद ही लागू करने की बात कही थी, जो 2026 के बाद होने की संभावना है। कई सामाजिक संगठनों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी है कि इतना लंबा इंतजार करना संविधान में निहित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। उनका कहना है कि 75 वर्षों बाद भी जब संसद में महिलाओं की संख्या 15 प्रतिशत से कम है, तब 'नारी शक्ति वंदन' को प्रतीक्षा की बेड़ियों में बांधकर रखना न्यायसंगत नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र से चार स्पष्ट सवालों के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि यदि आवश्यक हुआ, तो इस विषय पर व्यापक जनहित सुनवाई आयोजित की जा सकती है, क्योंकि यह मुद्दा देश की आधी आबादी की राजनीतिक भागीदारी से जुड़ा है — जो लोकतंत्र की आत्मा है।

नवसर्जन संस्कृति

हिन्दी

JioTV

CHENNAL NO. 2063

Jio Air Fiber

Jio Tv +

Jio Fiber

Daily Hunt

ebaba Tv

Dish Plus

DTH live OTT

Rock TV

Airtel

Amezone Fire

Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही नवसर्जन संस्कृति हिंदी चैनल देखिये

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में ‘भारत पर्व’ का प्रकाशमय उत्सव

एकता नगर जगमगा उठा प्रकाश के रंग से

- ▶▶ भारतीय शैली की कलरफुल लाइटिंग से झिलमिलती स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
- ▶▶ प्रकाश पर्व पैवेलियन में लाइटिंग के साथ ढेरों सेल्फी ले रहे पर्यटक
- ▶▶ एलईडी डाइनामिक लाइटिंग से प्रकृति एवं टेक्नोलॉजी के बीच परफेक्ट सिम्फनी रचती है
- ▶▶ लाइटिंग की जगमगाहट से प्रकाशित हुआ राष्ट्रीय एकता एवं प्रकृति के प्रति प्रेम
- ▶▶ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आकाशीय दृश्यों का अद्भुत नजारा पर्यटकों का आकर्षण
- ▶▶ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित जंगल सफारी, कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, सर्किट हाउस, एकता मॉल, एडमिन बिल्डिंग रंगबिरंगी लाइटिंग से जगमगाए

(जीएनएस)। गांधीनगर : भारतीय संस्कृति में प्रकाश को अंधकार दूर करने के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा एवं उत्साह के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। तीज-त्योहार तथा धार्मिक उत्सव में प्रकाश का स्थान महत्वपूर्ण एवं अडिग रहा है। आज के युग में लाइटिंग एक आर्ट बन गई है और भारतीय लाइटिंग शैली की झलक पेरिस के फेस्टिव ऑफ लाइट्स तथा दुबई के लाइट डोम शो में देखने को मिलती है। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में भारत पर्व का ऐतिहासिक उत्सव मनाया जा रहा है, तब एकता नगर कलरफुल लाइट्स के प्रकाश से जगमगा उठा है। प्रकाश पर्व के अवसर पर एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर प्रकाश से जगमगा उठा है। मानो एकता नगर दुल्हन की तरह साज सया है। समग्र क्षेत्र को विभिन्न रंगबिरंगी लाइटिंग से भारत की

विभिन्न संस्कृतियों तथा परंपराओं की झाँकियों से सजाया गया है, जहाँ भारत की विविधता में एकता के दर्शन होते हैं। 182 मीटर की बुनिया की सबसे ऊँची सरदार वल्लभभाई पटेल की भव्य प्रतिमा से लेकर सरदार सरोवर बांध तक हर स्थान पर तिरंगे रंग में लेसर लाइट से जगमगाहट छा गई है। प्रकाश के विभिन्न रंग भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता का प्रतीक बनकर खड़े हैं। स्थानीय कलाकारों व शिल्पकारों ने भी अपनी हस्तकला कृतियों को लाइटिंग के प्रकाश द्वारा प्रस्तुत किया है। इस लाइटिंग में आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ परंपरागत डिजाइन का समन्वय देखने को मिला है। लाइटिंग तथा फोटोग्राफी का संबंध इतना अविभाज्य है कि जहाँ प्रकाश हो, वहाँ कैमरा स्वयं आकर्षित होता है। भारत पर्व में लाइटिंग के साथ पर्यटकों ने हजारों सेल्फी एवं फोटो अपने मोबाइल में संजोए हैं। लाइटिंग से सजाई गई

हर थीम अपने भीतर कोई संदेश समेटे है। कहीं राष्ट्रीय एकता का प्रतिबिंब है, तो कहीं प्रकृति के प्रति प्रेम झलकता है। नर्मदा नदी की निर्मल धारा समान इस पर्व के उत्सव में देश के विभिन्न राज्यों की लोककला, लोकसंगीत, हस्तकला तथा भोजन की रसधारा बहती दिखाई देती है। हर राज्य ने अपने परंपरागत वेशभूषा तथा कला द्वारा देश की सांस्कृतिक समृद्धि को प्रस्तुत किया है, जिससे एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना जीवंत हो उठी है। इस भावना को उजागर करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से भारत पर्व का भव्य उत्सव नर्मदा नदी के पवित्र तट पर मनाया जा रहा है। आज के डिजिटल युग में लाइट फेस्टिवल जैसे प्रसंग सेल्फी कल्टर का हिस्सा बन गए हैं, जहाँ हर फोटो पर्यटकों को प्रकाश, आनंद तथा भारतीय संस्कृति की एक नई कहानी कहती है।



प्रकाश पर्व पैवेलियन में 5 प्रकार की एलईडी लाइटिंग टेक्नोलॉजी द्वारा डेकोरेटिव सुशोभन किया गया



एकता प्रकाश पर्व पैवेलियन में एलईडी लाइट्स, आरजीबी एलईडी नियोन फ्लेस स्ट्रिप लाइट्स, कलरफुल लेसर प्रोजेक्शन लाइट्स, स्मार्ट स्क्रिनाइज्ड लाइट्स, सॉलर पावर्ड लाइटिंग से रजवाड़ा शैली के आर्किटेक्चर में देखने को मिल रही फूलों की नाजूक कढ़ाई, स्वर्ण अलंकार, क्लासिकल आकारों की लाइटिंग की कृतियाँ एकता द्वार से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक के सात किलोमीटर के क्षेत्र की स्ट्रीट लाइट, ग्रेट्री मोटिफ्स, सस्कारी भवन, पर्यटन आकर्षण, सर्किट हाउस, एकता मॉल, एडमिन बिल्डिंग तथा मुख्य मार्ग पर स्थित पेड़ विभिन्न लिटिंग डेकोरेशन से सुशोभित किए गए हैं। मुख्य मार्ग से वैली ऑफ फ्लावर्स तक के 530 मीटर के मार्ग में सीलिंग लाइट्स, विभिन्न प्रकार के लाइटिंग आर्टिक्लस तथा थीम आधारित सेल्फी पॉइंट्स के साथ फ्लेट वूड्स आकाशगंगा की झाँकी देती दिखाई देती है। इसके साथ इसरो के मिशन चंद्रयान, ऑर्बिशन सिंदूर की थीम, पक्षी, प्राणी, कलात्मक रूप, पेड़, फूल, धार्मिक चिह्न, ग्रह तथा सौरमंडल के रूप में आध्यात्मिक भारत की अद्भुत संकल्पनाओं को प्रकाश के रूप में व्यक्त किया गया है। वैली ऑफ फ्लावर्स पैवेलियन में 140 मीटर लंबे वॉक-वे को ग्लो टनल में विभिन्न थीम आधारित कलरफुल लाइटिंग से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जंगल सफरी, कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, उत्तरवर्तिनी नर्मदा परिक्रमा, सोमनाथ, द्वारका, डाकोर जैसे विभिन्न धार्मिक स्थलों की थीम से कृतियाँ प्रदर्शित की गई हैं। सरदार सरोवर बांध में विशेष डिजाइन किए गए डाइनामिक लाइट एंड साउंड तथा सरदार पटेल की प्रतिमा पर शाम को लेसर शो का आयोजन किया गया है, जिसे देखने के लिए पर्यटकों में विशेष आकर्षण देखने को मिलता है।



छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से भेंट की वाइब्रेंट गुजरात समिट की सफलता तथा सीएम डैशबोर्ड से प्रभावित हुए साय

(जीएनएस)। गांधीनगर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से भेंट की। श्री साय एकता नगर में चल रहे भारत पर्व में सोमवार रात होने वाली छत्तीसगढ़ राज्य की विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए गुजरात यात्रा पर आए हैं।

वे आगामी समय में छत्तीसगढ़ में आयोजित होने जा रहे छत्तीसगढ़ इन्व्हेस्टर कॉन्फेंस में गुजरात के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मंगलवार को अहमदाबाद में उनके साथ बैठकें करने वाले हैं। इन कार्यक्रमों से पहले श्री साय ने सोमवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात की और गुजरात



प्रयोग द्वारा गुजरात के जिलों में औद्योगिक निवेशकों को प्रोत्साहित कर वोक्ल फॉर लोकल तथा लोकल टु ग्लोबल के उद्देश्य के साथ वर्ल्ड मार्केट देने के दृष्टिकोण से अवगत कराया। श्री साय ने गुजरात की इंडस्ट्रियल पॉलिसी की विस्तृत जानकारी के लिए प्रधान उद्योग सचिव सहित वरिष्ठ सचिवों के साथ भी बैठक की। इतना ही नहीं; उन्होंने गुजरात में पब्लिक डिलीवरी सर्विसेज सिस्टम तथा जन हितकारी योजनाओं की ट्रान्सपेरेंट एवं रीयल टाइम मॉनिटरिंग के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में इस वर्ष रीजनल वाइब्रेंट कॉन्फ्रेंस के

द्वारा वाइब्रेंट समिट की उत्तरोत्तर सफलता के चलते मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट का स्थान प्राप्त किए जाने के बारे में जानने में गहरी रुचि दर्शाई। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में इस वर्ष रीजनल वाइब्रेंट कॉन्फ्रेंस के नेटवर्क से निर्बाध ब्रॉड गेज संपर्क प्रदान होगा। इस रेल लाइन से पोर्ट कनेक्टिविटी में वृद्धि होगी तथा कच्छ जिले में बंदरगाहों के माध्यम से निर्यात-आयात को प्रोत्साहन मिलेगा। इस क्षेत्र के सीमेंट उद्योगों को भी इससे विशेष लाभ होगा और नमक, खनिज एवं अन्य कच्चे माल के कुशल परिवहन में सुगमता आएगी। भुज-नलिया रेल लाइन का आगे वायोरा तक (26.55 किमी) विस्तार का कार्य भी प्रगति पर है। इसके पूर्ण होने पर देश की सेना को सीमा क्षेत्र तक पहुँचने और सामान परिवहन में भी सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 27 अगस्त 2025 को देशलपार - हाजीपीर - लूना और वायोरा - लखपत नई लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रस्तावित नई रेल लाइन कच्छ क्षेत्र के सुदूर इलाकों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। यह गुजरात के मौजूदा रेलवे



नेटवर्क में 145 रूट किमी और जोड़ेगी, सीमेंट, कोयला, क्लिंफर और बेंटोनाइट के परिवहन में भी मदद करेगी। इस परियोजना का सामरिक महत्व यह है कि

के अलावा, यह नई रेल लाइन नमक, सीमेंट, कोयला, क्लिंफर और बेंटोनाइट के परिवहन में भी मदद करेगी। इस परियोजना का सामरिक महत्व यह है कि

यह कच्छ के रण को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। हड़प्पा स्थल धोलावीरा, कोटेश्वर मंदिर, नारायण सरोवर और लखपत किला भी रेल नेटवर्क के अंतर्गत आएंगे क्योंकि 13 नए रेलवे स्टेशन जोड़े जाएंगे जिससे 866 गाँवों और लगभग 16 लाख आबादी को लाभ होगा। इन विकासत्मक पहलों से क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, जिससे सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। गुजरात का गांधीधाम क्षेत्र पश्चिम रेलवे का अधिकतम माल लदान वाला क्षेत्र है यहाँ से अप्रैल 2025 से अक्टूबर 2025 तक औद्योगिक नमक का 1.727 मिलियन मीट्रिक टनT, खाद्य नमक का 1.119 मिलियन मीट्रिक टन और कंटेनर का 10.586 मिलियन मीट्रिक टन का लदान किया गया। जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। न्यू भुज स्टेशन का यह रूपांतरण न

गुजरात सरकार के उद्यमिता प्रशिक्षण से राज्य के जनजातीय बन रहे आत्मनिर्भर, पिछले 4 वर्षों में 120+ जनजातीय बने सफल उद्यमी

- ▶▶ पिछले 4 वर्षों में 2 करोड़ खर्च कर 1,000+ युवाओं को दिया उद्यमिता प्रशिक्षण
- ▶▶ उद्यमिता प्रशिक्षण के लिए राज्यभर में संचालित है 42 स्क्रिल अप-ग्रेडेशन सेंटर्स (SUCs) और 9 रीजनल सेंटर्स
- ▶▶ वर्ष 2021–22 से 2024–25 के बीच 1300+ जनजातीय युवाओं को मिला कौशल प्रशिक्षण, 223 लाभार्थियों को मिले रोजगार के अवसर

(जीएनएस)। गांधीनगर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “जनजातीय समाज को आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर करने” के विचार मंत्र को आधार बनाकर गुजरात सरकार राज्य के आदिवासी समाज के आर्थिक सशक्तिकरण, और आत्मनिर्भरता के लिए कई गहन प्रयास कर रही है। गुजरात के उद्योग आयुक्त कार्यालय के अंतर्गत कार्यरत उद्यमिता विकास केंद्र (CED गुजरात) द्वारा जनजातीय युवाओं के कौशल, रोजगार और उद्यमिता विकास को गति देने के लिए कई वर्षों से उद्यमिता प्रशिक्षण और कौशल विकास की सुविधा दी जा रही है।

4 वर्षों में 1,000+ युवाओं को उद्यमिता प्रशिक्षण, 2 करोड़ खर्च, 120 बने सफल उद्यमी

पिछले चार वर्षों (2021-22 से 2024-25) में गुजरात सरकार, उद्योग आयुक्तालय के अधीन कार्यरत सेंटर फॉर ऑन्ट्रेप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट (CED) ने 14 से अधिक जनजातीय जिलों में ऑन्ट्रेप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम (EDP) और जागरूकता कार्यक्रमों को माध्यम से हजारों युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सशक्त रूप से प्रेरित किया है। उल्लेखनीय है कि गुजरात सरकार की इस विशेष पहल के द्वारा हर साल आदिजाति क्षेत्र के लगभग 200 से अधिक युवाओं को विभिन्न उद्यमिता से संबंधित प्रोफेशनल ट्रेनिंग की सुविधा दी जाती है जिससे राज्य के आदिवासी जिलों के लगभग 30 से अधिक प्रशिक्षु स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। बीते 4 वर्षों में राज्य सरकार ने 2 करोड़ खर्च कर 1000+ आदिजाति युवाओं को उद्यमिता प्रशिक्षण की सेवाएँ दी है। इनमें से 120+ युवा अब अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालित करते हुए आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इसी तरह कौशल विकास के प्रयास के तहत 2021-22 से 2024-25 के दौरान 1300+ जनजातीय युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया। उल्लेखनीय है कि पिछले तीन वर्षों में 223 आदिजाति युवाओं को प्रशिक्षण के पश्चात प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।

गुजरात सरकार के प्रयासों से जनजातीय युवा बन रहे आत्मनिर्भरता की मिसाल

गुजरात में कौशल विकास और उद्यमिता प्रशिक्षण के प्रभाव अब जमीन पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। वलसाड जिले के गुंडलव GIDC में श्री हितेश पटेल ने भी राज्य सरकार के CED से बिजनेस डेवलपमेंट प्रशिक्षण के बाद स्टैंडर्ड इक्विपमेंट संस्था की स्थापना की। रासायनिक उद्योग में उपयोग होने वाले प्रोसेस पंपों के निर्माण में उनकी कंपनी अब अग्रणी बन चुकी है। आदित्य बिड़ला ग्रुप और MERCK जैसे दिग्गज ग्राहक, 15 सदस्यों की टीम और 3 करोड़ का वार्षिक कारोबार स्पष्ट करता है कि कौशल-आधारित उद्यमिता क्षेत्रीय औद्योगिक विकास के लिए कितनी निर्णायक साबित हो सकती है। डांग की जनजातीय बस्ती की श्रीमती दक्षाबेन बिरारी ने CED के प्रशिक्षण और सखी मंडल के सहयोग से अंबिका हलदर फार्म स्थापित कर पारंपरिक हल्दी खेती को आधुनिक एग्रो-बिजनेस में बदला।

क्या है जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए गुजरात का उद्यमिता प्रशिक्षण मॉडल?

गुजरात सरकार के उद्यमिता प्रशिक्षण मॉडल में 42 स्क्रिल अप-ग्रेडेशन सेंटर्स, एंकर इन्स्टीट्यूट्स, उद्योग आधारित ब्रिज कोर्सेस और स्पेशलाइज्ड स्क्रिल डेवलपमेंट सेंटर को मिलाकर एकीकृत और मजबूत व्यवस्था विकसित की गई है। आधुनिक उपकरणों, स्मार्ट क्लासरूम और स्थानीय उद्योगों के साथ साझेदारी के माध्यम से इन केंद्रों को इस प्रकार सक्षम बनाया गया है कि प्रशिक्षण सीधे उद्यमिता और रोजगार में परिवर्तित हो सके। ये प्रशिक्षण कोर्स कई क्षेत्रों रासायनिक प्रसंस्करण, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान और सिलाई, सौंदर्य एवं बेलनेस, लॉजिस्टिक्स, आईटी और डेटा एंटी, तथा नवीकरणीय ऊर्जा सहित को कवर करते हैं। राज्य सरकार का कहना है कि इन कोर्सों का पाठ्यक्रम स्थानीय आर्थिक संभवनाओं और उद्योग की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है।

केवल रेल यात्रियों के लिए बल्कि स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा। भुज स्टेशन को आगामी 40 से 50 वर्षों तक की कच्छ क्षेत्र की यात्रा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पुनर्विकसित किया जा रहा है। **परियोजना की प्रमुख विशेषताएँ एवं लाभ:** ▶▶ मुख्य स्टेशन भवन: लगभग 1.37 लाख वर्गफुट क्षेत्र में तथा द्वितीय प्रवेश भवन 11,600 वर्गफुट क्षेत्र में बनाया जा रहा है, जिससे यात्रियों की आवाजाही और सुगमता में वृद्धि होगी। ▶▶ आधुनिक वेंटिंग एरिया कांंकसं: 8,000 वर्गफुट में 450 से अधिक यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी, जिससे प्रतीक्षा के दौरान आरामदायक रहेगा। ▶▶ विशाल कांंकसं: (35,000 वर्गफुट) यात्रियों के आवागमन को सुविधाजनक बनाएगा और भीड़-प्रबंधन में सहायता करेगा।

▶▶ सुगम संपर्क व्यवस्था: स्टेशन पर कुल 3 फुट ओवरब्रिज (FOB) बनाए जा रहे हैं, जिनमें दो 6 मीटर चौड़े एवं एक 8 मीटर चौड़ा है। इससे प्लेटफॉर्मों के बीच यात्रियों की आवाजाही और अधिक सुरक्षित एवं आसान होगी। ▶▶ प्लेटफॉर्म उन्नयन: लगभग 1.32 लाख वर्गफुट क्षेत्र जिसमें 1.20 लाख वर्गफुट की छतयुक्त संरचना यात्रियों को हर्ष मौसम में सुविधा प्रदान करेगी। ▶▶ हरित एवं स्मार्ट अवसंरचना: 500 KWP सौर ऊर्जा संयंत्र, वर्षा जल संचयन प्रणाली, 560 KLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा 32,000 वर्गफुट से अधिक हरित क्षेत्र का विकास पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाएगा। ▶▶ उन्नत यात्री सुविधाएँ: 13 लिफ्ट, 10 एस्केलेटर, आधुनिक फायर डिटेक्शन सिस्टम, 250 टन क्षमता का HVAC

सिस्टम (Heating, Ventilation and Air Conditioning), CCTV निगरानी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल, SCADA (Automatic Chemical Agent Detection and Alarm) और Wi-Fi सुविधा से यात्रियों को सुरक्षा, सुविधा और कनेक्टिविटी का समन्वय मिलेगा। ▶▶ पार्किंग सुविधा: स्टेशन के दोनों ओर 50 से अधिक कारों, 400 से अधिक दोपहिया वाहनों, 30 ऑटो रिक्शा और 4 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था की जा रही है, जिससे यात्रियों और स्थानीय नागरिकों को बेहतर पार्किंग अनुभव मिलेगा। ▶▶ पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता: हरित भवन प्रमाणन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, साथ ही परिसर में वृक्षारोपण एवं पौधारोपण से स्वच्छ और हरित वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात की लोक कला और लोक संस्कृति के प्रहरी पद्मश्री दिवंगत जोरावरसिंह जादव को श्रद्धासुमन अर्पित किए

गुजरात यूनिवर्सिटी में दिवंगत जोरावरसिंह जादव की प्रार्थना सभा आयोजित हुई

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात की जीवंत लोक कलाओं, लोक जीवन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को 110 से अधिक पुस्तकों के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल विरासत के रूप में छोड़ जाने वाले सुप्रसिद्ध लेखक, शोधकर्ता और पद्मश्री पुरस्कार विजेता दिवंगत जोरावरसिंह जादव की प्रार्थना सभा सोमवार को अहमदाबाद स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी में आयोजित हुई। राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस प्रार्थना सभा में उपस्थित रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धासुमन अर्पित किए। दिवंगत जोरावरसिंह जादव लेखक और लोक कलाकारों के जीवंत संरक्षक थे। आकरं गांव से शुरू हुई लोक कला संवर्धन की उनकी अनूठी यात्रा गुजरात



के सांस्कृतिक इतिहास का एक विशिष्ट अध्याय है। दिवंगत जोरावरसिंह जादव को वर्ष 2019 में भारत सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएँ दी थीं।

इसके अलावा, उन्होंने गुजराती लोक संग्रहालय ‘विरासत’ का सृजन किया, जिसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने ही किया था। प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में लोक कलाकार, साहित्यकार, नागरिक और उनके प्रशंसकों ने उपस्थित रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की।

